19/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'किसी भी स्तर पर' ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना असंभव है (19 अप्रैल) (GS PAPER II: चुनाव)**
2. **'भारत में बेचे जाने वाले नेस्ले बेबी फूड में चीनी की मात्रा अधिक है (19 अप्रैल) (GS PAPER II: गवर्नेंस)**
3. **अव्यवस्थित दुनिया, भविष्य के बारे में चिंता (19 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)**
4. **का युद्ध (19 अप्रैल) (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)**
5. **दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण (19 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)**

'भारत में बेचे जाने वाले नेस्ले बेबी फूड में चीनी की मात्रा अधिक है (19 अप्रैल) (GS PAPER II: गवर्नेंस)

- **स्विस एनजीओ, पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फ़ूड एक्शन नेटवर्क** की एक रिपोर्ट पाया गया कि नेस्ले का बेबी फ़ूड **भारत, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचा जाता है** इसमें यूरोप में बेचे जाने वाले समान उत्पादों की तुलना में अधिक चीनी है।
- **खाद्य सुरक्षा मानक तय करने वाली संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण इस रिपोर्ट की जांच कर रही है** ।
- इसका मतलब यह है कि कुछ क्षेत्रों में बेचे जाने वाले शिशु आहार उत्पादों में चीनी की मात्रा अधिक हो सकती है, जिससे शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
- भारत, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जाने वाले नेस्ले के शिशु आहार उत्पादों में यूरोपीय बाज़ारों में बिकने वाले उत्पादों की तुलना में अधिक चीनी होती है।
- स्विस एनजीओ, पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (आईबीएफएएन) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
- नेस्ले के लगभग 150 शिशु उत्पादों का बेल्जियम की प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया।

PatrioticIAS

- उदाहरण के लिए, **छह महीने के बच्चों के लिए सेरेलैक उत्पाद, जिसमें यूके और जर्मनी में कोई अतिरिक्त चीनी नहीं होती है, भारत में प्रति सेवारत 2.7 ग्राम अतिरिक्त चीनी होती है।**
- इथियोपिया और थाईलैंड में, उन्हीं उत्पादों में **प्रति सेवारत लगभग 6 ग्राम अतिरिक्त चीनी थी।**
- यह कुछ क्षेत्रों में शिशु आहार में उच्च चीनी सामग्री के स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है।

चीनी में कटौती

- तीन साल से कम उम्र के बच्चों के भोजन में अतिरिक्त चीनी के खिलाफ डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के बावजूद, भारतीय नियामक शिशु आहार में सीमित सुक्रोज और फ्रुक्टोज की अनुमति देते हैं।
- नेस्ले इंडिया ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अतिरिक्त शर्करा को कम करना प्राथमिकता है।
- पिछले पांच वर्षों में, नेस्ले इंडिया ने अपने शिशु अनाज उत्पादों में अतिरिक्त शर्करा को 30% तक कम करने का दावा किया है।
- नेस्ले इंडिया इस बात पर जोर देती है कि उसके उत्पाद बचपन के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और आयरन के साथ उचित पोषण सुनिश्चित करते हैं।
- कंपनी पोषण गुणवत्ता और वैश्विक और स्थानीय मानकों के अनुपालन से समझौता नहीं करने का वचन देती है।
- वे नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और पोषण, गुणवत्ता, सुरक्षा या स्वाद से समझौता किए बिना अतिरिक्त शर्करा को कम करने के लिए नवाचार करते हैं।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण IBFAN रिपोर्ट की जांच कर रहा है।
- ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के अरुण गुप्ता जैसे विशेषज्ञ स्वास्थ्य जोखिमों के कारण दो साल से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त चीनी या नमक देने के खिलाफ चेतावनी देते हैं।
- डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि बच्चों के भोजन में चीनी मिलाने से उन्हें खाने की लत लग सकती है और कम उम्र से ही वे मीठे स्वाद को प्राथमिकता दे सकते हैं।

'दोहरा मापदंड'

- हेपेटोलॉजिस्ट सिरिएक एबी फिलिप्स, जिन्हें सोशल मीडिया पर द लिवर डॉक के नाम से जाना जाता है, ने नेस्ले पर "दोहरे मानदंड" रखने का आरोप लगाया।
- उन्होंने विशेष रूप से नेस्ले के बेबी फूड उत्पाद, सेरेलैक का उल्लेख किया, जिसकी वैश्विक खुदरा बिक्री एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- फिलिप्स ने बताया कि सेरेलैक की बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से 40%, ब्राजील और भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में है।
- उन्होंने एशियाई बाजारों की तुलना में पश्चिमी बाजारों में अपने उत्पादों के लिए अलग मानक रखने के लिए नेस्ले की आलोचना की।
- इससे पता चलता है कि नेस्ले के पास क्षेत्र के आधार पर सेरेलैक के लिए अलग-अलग उत्पाद फॉर्मूलेशन या गुणवत्ता मानक हो सकते हैं, जिसे फिलिप्स अनुचित मानता है।

PatrioticIAS

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'किसी भी स्तर पर' ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना असंभव है (19 अप्रैल) (GS PAPER II: चुनाव)

- चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
- लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले चुनाव आयोग ने यह आश्वासन दिया था.
- सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित विभिन्न समूहों की उन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जो ईवीएम के साथ या उसके बिना, अधिक पारदर्शी चुनावी प्रणाली के लिए बहस कर रही हैं।
- सुनवाई के दौरान कागजी मतपत्रों की वापसी या उम्मीदवारों के लिए बार कोड लागू करने जैसे विचारों पर चर्चा की गई।
- अधिवक्ताओं ने मतदाताओं द्वारा यह पुष्टि करने में सक्षम होने के महत्व पर प्रकाश डाला कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है।
- याचिकाओं में वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पेपर पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग की गई थी।
- वर्तमान में, एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों पर ईवीएम-वीवीपीएटी का क्रॉस-सत्यापन होता है।
- चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक यादृच्छिक सत्यापन के 41,629 मामले सामने आए हैं, जिसमें चार करोड़ से अधिक वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान किया गया है, और बेमेल का कोई मामला नहीं पाया गया।

बहुत बड़ा प्रयास

- चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा कि एक मतदान केंद्र के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की मैन्युअल गिनती में एक घंटा लगेगा।
- प्रत्येक मतदान केंद्र पर आमतौर पर लगभग 1,000 वीवीपैट पर्चियों की गिनती की आवश्यकता होती है।
- कागज का छोटा आकार और विशिष्ट प्रकृति पर्चियों को चिपचिपा बना देती है, जिससे मैन्युअल गिनती प्रक्रिया की जटिलता बढ़ जाती है।
- चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी बोझिल प्रकृति के कारण इस प्रक्रिया को तेज या जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है।
- चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 से 2024 तक मतदाताओं और वोटिंग मशीनों दोनों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में मतपत्र इकाइयाँ, नियंत्रण इकाइयाँ और वीवीपीएटी शामिल होती हैं, इन सभी को उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में सील कर दिया जाता है और मतदान के बाद 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में संग्रहीत किया जाता है।

PatrioticIAS

केरल में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें झूठी हैं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया (19 अप्रैल)

- भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केरल में मॉक पोल के दौरान चार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से भाजपा के लिए गलती से वोट पड़ने के बयान झूठे थे।
- **याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने 17 अप्रैल को कासरगोड जिले में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में खराबी की खबरों की ओर ध्यान दिलाया।**
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता शामिल थे, ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से दावों को सत्यापित करने के लिए कहा।
- जाँच के बाद, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी, नितेश कुमार व्यास ने अदालत को पुष्टि की कि समाचार रिपोर्टें झूठी थीं।
- चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर के साथ आरोपों का सत्यापन किया और उन्हें असत्य पाया।
- चुनाव आयोग ने मामले के संबंध में अदालत को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का वादा किया।
- याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को स्पष्ट किया कि उन्होंने अदालत को केवल ईवीएम मुद्दे के संबंध में मीडिया रिपोर्टों के बारे में सचेत किया था और उनके इरादे प्रतिकूल नहीं थे।
- न्यायमूर्ति खन्ना ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने केवल मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा किया था और इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित नहीं किया था।
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के 100% क्रॉस-सत्यापन का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित याचिकाकर्ता अदालत से आग्रह कर रहे हैं कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियों तक भौतिक पहुंच की अनुमति दी जाए ताकि पर्चियों को सीलबंद मतपेटियों में डालने से पहले उनके द्वारा डाले गए वोटों की पुष्टि की जा सके।
- उनका तर्क है कि मतदाताओं को अपने वोटों की सटीकता के बारे में आश्वस्त होना मौलिक अधिकार है।
- याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि ईवीएम में खराबी हो सकती है या दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जो संभवतः किसी विशेष पार्टी, संभवतः सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो सकती है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (केरल) संजय कौल ने उन शिकायतों को खारिज कर दिया कि ईवीएम में भाजपा के लिए अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए थे, उन्होंने कहा कि मॉक पोल के दौरान वीवीपैट मशीन द्वारा जारी एक अतिरिक्त पर्ची से गलतफहमी पैदा हुई थी।
- सामान्य वीवीपैट पर्चियों की तुलना में लंबी अतिरिक्त पर्ची का उपयोग मॉक पोल से पहले प्रारंभिक निरीक्षण के लिए किया जाता है और इस पर 'मानकीकरण हो गया' और वीवीपैट सीरियल नंबर के साथ 'गिनती नहीं की जाएगी' लिखा होता है।

यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण : (19अप्रैल)

PatriotIAS

- जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू की, उनकी विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद, 1936 में स्विस सेनेटोरियम में तपेदिक (टीबी) से मृत्यु हो गई।
- उस समय नेहरू जेल में थे और औपनिवेशिक बंधनों के कारण उनके साथ रहने में असमर्थ थे।
- एमए जिन्ना, जो बाद में नेहरू के राजनीतिक विरोधी बन गए, की भी टीबी से मृत्यु हो गई, जिसने इस बीमारी की अंधाधुंध प्रकृति को उजागर किया।
- दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ-साथ उनकी मौतें, 1882 में इसकी खोज के बावजूद, टीबी के लिए प्रभावी उपचार की कमी को रेखांकित करती हैं।
- आज, दशक के अंत तक इस बीमारी को ख़त्म करने के प्रयासों के साथ, टीबी के उपचार में काफी सुधार हुआ है।
- 2024 में विश्व टीबी दिवस का विषय "हां, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं" था, जो चिकित्सा प्रगति और चिकित्सा समुदाय के प्रयासों से संभव हुई प्रगति को दर्शाता है।

इलाज में क्रांति

- क्षय रोग (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और कम से कम 3 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है, जो मानवता के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती है।
- एंटीबायोटिक दवाओं से पहले, टीबी उपचार उपशामक देखभाल पर केंद्रित था, जैसे कि उच्च ऊंचाई या शांत ग्रामीण इलाकों में सेनेटोरियम में ताजी हवा और आराम प्रदान करना।
- लोबेक्टोमी, कृत्रिम न्यूमोथोरैक्स और न्यूमोनेक्टॉमी जैसी सर्जिकल प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया गया लेकिन सीमित सफलता मिली।
- सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एंटीबायोटिक दवाओं की खोज ने टीबी के इलाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।
- सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल ने चिकित्सा सांख्यिकी में अग्रणी और ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल (बीएमआरसी) में यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण तकनीक की शुरुआत करके टीबी के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- हिल के काम से टीबी के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने वाले पहले यादृच्छिक नैदानिक परीक्षणों में से एक का नेतृत्व किया गया।
- उन्होंने चिकित्सा में वैज्ञानिक अखंडता के लिए एक नया मानक स्थापित करते हुए, नैदानिक परीक्षणों के लिए प्रारंभिक नैतिक दिशानिर्देश भी स्थापित किए।

अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका

- यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षणों (आरसीटी) ने विभिन्न उपचारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक निष्पक्ष विधि प्रदान करके आधुनिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- आरसीटी ने कई चिकित्सा सफलताओं को जन्म दिया है, जैसे दिल के दौरे को रोकने में एस्पिरिन की भूमिका की खोज करना, एचआईवी के लिए एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी विकसित करना, और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी लागू करना, साथ ही साथ सीओवीआईडी टीकों का विकास।
- टीबी के खिलाफ प्रभावी पहला एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के परीक्षण में सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल द्वारा आरसीटी का प्रभावी उपयोग अभूतपूर्व था।
- उनके काम ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की इष्टतम खुराक स्थापित करने में मदद की, इसे प्रयोगशाला की खोज से टीबी उपचार के लिए व्यावहारिक समाधान में बदल दिया।

PatrioticIAS

- हिल के प्रयासों ने टीबी के प्रबंधन को विशेष सर्जनों से लेकर प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों तक विस्तृत कर दिया।
- हिल का योगदान टीबी से आगे बढ़कर आधुनिक महामारी विज्ञान तक बढ़ा, उनके "ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया" ने कारकों और स्वास्थ्य प्रभावों के बीच कारण संबंध स्थापित करने का आधार बनाया।
- नौ मानदंडों ने सबूतों की जांच के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया, जैसे शराब को हृदय रोगों के लिए जोखिम कारक के रूप में स्थापित करना और धूम्रपान को फेफड़ों के कैंसर से जोड़ना।
- धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर पर हिल के शोध ने अकाट्य साक्ष्य प्रदान किए, जो तंबाकू उद्योग द्वारा प्रचारित छद्म विज्ञान को चुनौती देते हैं और तंबाकू के प्रति सार्वजनिक धारणा और नीति को प्रभावित करते हैं।

कर्ज देने वाले का आभारी

- मल्टी-ड्रग ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) और एक्सटेंसिवली ड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एक्सडीआर-टीबी) जैसी चुनौतियों के बावजूद, हम टीबी को खत्म करने के करीब हैं।
- हम सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल के योगदान के लिए उनके प्रति बहुत आभारी हैं।
- हिल का जीवन और कार्य वैज्ञानिक जांच और लचीलेपन के महत्व को प्रदर्शित करता है।
- जब हम टीबी उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे हैं तो वह हमें प्रेरित करते हैं।
- आइए हिल जैसे वैज्ञानिकों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करें।
- उनके शोध और ज्ञान की खोज ने अविश्वसनीय परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।
- हिल का कार्य सकारात्मक परिवर्तन लाने की विज्ञान की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
- उनकी विरासत दुनिया भर के शोधकर्ताओं को प्रेरित करती रहती है।

अव्यवस्थित दुनिया, भविष्य के बारे में चिंता (19 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)

दुनिया भर में प्रभाव रखने वाले नेताओं की अनुपस्थिति, नए गठबंधन, आर्थिक मुद्दे और वर्तमान प्रौद्योगिकियों की प्रगति कुछ कारक हैं

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)

- उत्तरी अटलांटिक संधि के आधार पर 1949 में एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन की स्थापना की गई।
- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स, बेल्जियम

PathIAS

- **वर्तमान सदस्यता:** यूरोप और उत्तरी अमेरिका से 30 देश।
- **संस्थापक सिद्धांत:** संधि के **अनुच्छेद 5 में** कहा गया है कि एक सहयोगी पर हमला सभी पर हमला है, जो **सामूहिक रक्षा की अवधारणा को दर्शाता है।**

मूल उद्देश्य

- **संकट प्रबंधन:** नाटो क्षेत्र के बाहर सहित संघर्ष क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए संचालन में संलग्न होना।
- **सहकारी सुरक्षा:** गैर-सदस्य देशों के साथ साझेदारी और सहयोग बनाना, स्थिरता को बढ़ावा देना।

हाल के फोकस क्षेत्र

- **रूसी आक्रमण:** विशेष रूप से क्रीमिया पर कब्जे के बाद पूर्वी यूरोप में बढ़ी रूसी सैन्य गतिविधि के खिलाफ प्रतिरोध।
- **साइबर सुरक्षा:** इस उभरते खतरे वाले क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अस्थिरता को संबोधित करता है।
- **उभरती और विघटनकारी प्रौद्योगिकियां (ईडीटी):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकियों के रणनीतिक निहितार्थों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि सहयोगी तकनीकी बढ़त बनाए रखें।

- बहुत से लोग वास्तव में इस बात से चिंतित हैं कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है।
- **ज़ेलेंस्की (यूक्रेन), नेतन्याहू (इज़राइल), और पुतिन (रूस)** जैसे नेता संघर्षों को ख़त्म करने की कोशिश न करने और परिणामों के बारे में न सोचने के लिए आलोचना की जा रही है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका मुश्किल स्थिति में है क्योंकि वे रूस को हराने के लिए नाटो का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है।
- नेतन्याहू पर गाजा में लोगों पर बहुत अधिक कठोर होने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है।
- इन सबके कारण ईरान इस क्षेत्र में और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

बढ़ती अराजकता, अनुपस्थित नेतृत्व

- 2022 के बाद से वैश्विक राजनीति अराजक रही है।
- **पश्चिम द्वारा बनाई गई "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" अब लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसने कुछ समय के लिए शांति बनाए रखने में मदद की है।**
- **पश्चिम कमजोर हो गया और चीन मजबूत हो गया, जिससे नए गठबंधन बने, लेकिन उनमें से कोई भी वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।**
- आज, दुनिया के कई हिस्सों में अराजकता है, यूक्रेन और गाजा जैसी जगहों पर युद्ध हो रहे हैं।

- आस-पास ऐसे कई नेता नहीं हैं जो शांति ला सकें और कई देशों पर प्रभाव डाल सकें, जैसे शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन या जो बिडेन।
- अधिकांश अन्य पश्चिमी नेताओं के पास भी शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, और वे अपने देशों को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इनमें से कई नेता इतिहास द्वारा भुला दिए जा सकते हैं क्योंकि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं।
- यूक्रेन में हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं. ज़ेलेंस्की, पुतिन और पश्चिम किसी समझौते पर सहमत नहीं हो सकते।
- **यह पहले से ही दो साल से चल रहा है, और ऐसा लगता है कि यह 2024 में भी जारी रहेगा।**
- **इस बात की चिंता है कि अगर गतिरोध जारी रहा तो नेता परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं।**
- पश्चिम एशिया में हालात गंभीर होते जा रहे हैं. इजराइल आक्रामक तरीके से काम कर रहा है, खासकर गाजा के प्रति।
- ईरान अब सीधे तौर पर इज़रायल को धमकी दे रहा है, और यह डर है कि ईरान पश्चिम और अन्य अविश्वासियों के खिलाफ आतंकवादी समूहों का नेतृत्व कर सकता है।
- यदि ईरान और इज़राइल पूर्ण युद्ध में समाप्त होते हैं, तो इसके वास्तव में बुरे परिणाम हो सकते हैं।

गठबंधनों का एक नया सेट

- **यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों की तुलना में महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता कम महत्वपूर्ण लगती है।**
- **अमेरिका और चीन सीधे टकराव के बजाय प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं।**
- **अफगानिस्तान जैसे झटके के बाद अमेरिका संघर्ष कर रहा है और यूरोप भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है.**
- **चीन की आर्थिक समस्याओं ने उसे महाशक्ति का दावेदार नहीं बना दिया है।**
- **चीन, रूस और ईरान मिलकर पश्चिम एशिया में अमेरिका और पश्चिम की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं।**
- विश्व नेता अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो वैश्विक राजनीति को चलाने वाले मुख्य कारक हैं।
- विशेषज्ञ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में समस्याओं की चेतावनी देते हैं।

विघ्न डालने वाले

- गठबंधन **से पता चलता है कि तेल की राजनीति जल्द ही एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा बन जाएगी।**
- **आर्थिक प्रतिबंध अपनी प्रभावशीलता खो रहे हैं** , और विशेषज्ञ एक बड़ी आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी करते हैं।
- प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), युद्ध में एक बड़ा व्यवधान बन रही है।**
- छोटे देश **AI का उपयोग कर रहे हैं** अमेरिका और चीन जैसी बड़ी सैन्य शक्तियों को चुनौती देने के लिए।
- यूक्रेन में **ड्रोन और निगरानी प्रणाली जैसी नई सैन्य तकनीक** युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रहा है।

PatrioticIAS

- हथियार नियंत्रण समझौते टूटने के साथ, संभवतः नए परमाणु हथियार विकसित किए जा रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध की चिंता बढ़ रही है।
- इस बात पर बहस चल रही है कि क्या अमेरिका और पश्चिम को रूस द्वारा निम्न-स्तरीय परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जवाब अपने परमाणु हथियारों से देना चाहिए।

का युद्ध (19 अप्रैल) (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

- माओवादी विद्रोह के खिलाफ संघर्ष, जो 2000 के दशक की शुरुआत से मध्य तक चरम पर था, एक पैटर्न में बस गया है।
- अर्धसैनिक और पुलिस बलों के हालिया हमलों ने विद्रोहियों को करारा झटका दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कम से कम 29 माओवादियों की हत्या भी शामिल है।
- माओवादी मुख्य रूप से **मध्य भारत के जंगलों और विरल जनजातीय उपस्थिति वाले क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जहां विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य कमजोर है।**
- हालाँकि माओवादियों ने राजनीतिक-वैचारिक प्रभाव खो दिया है, फिर भी वे सुरक्षा बलों के लिए खतरा बने हुए हैं, जैसा कि अर्धसैनिक बलों पर हाल के हमलों में देखा गया है।
- सुरक्षा बल माओवादी कैडरों को निशाना बनाने के लिए अपरंपरागत सैन्य रणनीति और नए मार्गों का उपयोग कर रहे हैं।
- हालाँकि, ये हमले अकेले माओवादी खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, **क्योंकि वे कठिन इलाकों में काम करते हैं और उन्हें गृहयुद्ध से प्रभावित कुछ असंतुष्ट आदिवासी वर्गों का समर्थन प्राप्त है।**
- भारतीय राज्य दो दशकों से माओवादियों से लड़ रहा है, खासकर दो नक्सली पार्टियों के सीपीआई (माओवादी) में विलय के बाद।
- प्रारंभ में, सलवा जुडूम जैसे अभियानों के माध्यम से आदिवासियों को हथियारबंद करने जैसी रणनीतियों का उल्टा असर हुआ, जिससे दृष्टिकोण में बदलाव आया।
- **माओवादी प्रचार का मुकाबला करते हुए, पहले से दुर्गम क्षेत्रों में कल्याणकारी राज्य और नौकरशाही की पहुंच का विस्तार करने** पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
- कल्याणकारी उपायों के इस विस्तार से कुछ जनजातीय समर्थन हासिल करने में मदद मिली और अन्य राज्यों में माओवादियों का पलायन हुआ।
- हालाँकि, छत्तीसगढ़ में, निरंतर युद्ध ने माओवादियों को आदिवासियों के बीच कुछ असंतोष का फायदा उठाने की अनुमति दे दी है।
- **नागरिक समाज और शांति कार्यकर्ताओं ने माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच युद्धविराम वार्ता शुरू करने की कोशिश की है और विद्रोहियों को लोकतांत्रिक तरीकों से आदिवासी हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।**
- असफलताओं के बावजूद, **माओवादियों ने अपनी विचारधारा को छोड़ने और संघर्ष को जारी रखने से इनकार कर दिया है, यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कई गरीब आदिवासी हिंसक तख्तापलट के बजाय कल्याण और चुनावी प्रणाली से बेहतर जुड़ाव और परिणाम चाहते हैं।**

हल्के हरे अंकुर (19 अप्रैल)

PatriotiAS

- **पिछले महीने 41.7 अरब डॉलर** के 12 महीने के शिखर पर पहुंच गया ।
- यह आंकड़ा मार्च 2023 से थोड़ा कम लेकिन फरवरी के 41.4 अरब डॉलर से ज्यादा था।
- **आयात 6% घटकर $57.3 बिलियन हो गया** , जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।
- पिछले दो महीनों में मजबूत निर्यात संख्या ने पूरे वर्ष के लिए कुल $437.1 बिलियन के आउटबाउंड शिपमेंट में योगदान दिया।
- **2022-23 में $451 बिलियन के रिकॉर्ड प्रदर्शन से** सिर्फ 3% कम है ।
- कमोडिटी की कीमतों में गिरावट, जो पिछले साल औसतन लगभग 14% कम थी, ने इस परिणाम में योगदान दिया।
- प्रमुख बाजारों में मांग अनुमान से अधिक लचीली साबित हुई।
- आयात में 4.8% की उच्च गिरावट ने भी व्यापार घाटे को कम करने में मदद की।
- अर्थशास्त्रियों को छोटे **चालू खाते के अधिशेष की आशा है** जनवरी-मार्च तिमाही के लिए.
- पूरे वर्ष के लिए सेवा व्यापार डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि 2023-24 में कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक 776.7 बिलियन डॉलर होगा।
- व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि **यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक संघर्षों के बावजूद माल निर्यात में सकारात्मक वृद्धि चक्र का अनुभव हो रहा है।**
- विश्व **व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने नकारात्मक जोखिमों का हवाला देते हुए अपने वैश्विक व्यापार मात्रा वृद्धि अनुमान को 3.3% के पहले अनुमान से संशोधित कर 2.6% कर दिया।**
- गिरावट के बावजूद, एशिया से निर्यात मात्रा 2024 में 3.4% बढ़ने की उम्मीद है, आयात 5.6% बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत में, स्वस्थ मानसून से विवेकाधीन आयात सहित घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- हालाँकि, **स्वेज़ और पनामा नहरों जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में लगातार व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार के लाभों के बारे में बढ़ते संदेह संभावित जोखिम पैदा करते हैं।**
- निर्यातक आशावादी आधिकारिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चित हैं और **बढ़ती शिपिंग लागत की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है** , जिससे प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ जाएगा।
- एशिया के तेल और गैस आयात के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग, **होर्मुज जलडमरूमध्य** में लंबे समय तक घर्षण , व्यापार और व्यापक आर्थिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।
- बढ़ोतरी **के कारण भारत का पेट्रोलियम व्यापार घाटा 11.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया** , जबकि तेल निर्यात घटकर आठ महीने के निचले स्तर पर आ गया।
- ऊर्जा आयात पर भारत की उच्च निर्भरता का मतलब है कि वैश्विक ऊर्जा और खाद्य कीमतों में कोई भी वृद्धि वैश्विक ब्याज दर में कटौती और बेहतर मांग की उम्मीदों को बाधित कर सकती है।

दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण (19 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)

यूएनसीएलओएस

- अक्सर "महासागरों के लिए संविधान" कहा जाता है, UNCLOS सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने वाला एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- यह कन्वेंशन 1982 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 1994 में लागू हुआ।

patriotIAS

- **व्यापक भागीदारी:** वर्तमान में, 168 पार्टियों (167 राज्यों और यूरोपीय संघ) ने कन्वेंशन की पुष्टि की है।

UNCLOS के प्रमुख प्रावधान

- **समुद्री क्षेत्र:** देश के समुद्र तट से फैले विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित करता है और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर अधिकार और कर्तव्य स्थापित करता है:
  - प्रादेशिक सागर (12 समुद्री मील तक): तटीय राज्य की संप्रभुता।
  - सन्निहित क्षेत्र (24 समुद्री मील तक): सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य कानूनों को लागू करने के लिए सीमित क्षेत्राधिकार
  - विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) (200 समुद्री मील तक): प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने, दोहन और प्रबंधन करने का अधिकार

  - महाद्वीपीय शेल्फ: यदि कुछ मानदंड पूरे होते हैं तो ईईजेड से परे भी समुद्र तल और उपमृदा संसाधनों पर अधिकार।
  - उच्च समुद्र: नेविगेशन, ओवरफ़्लाइट, मछली पकड़ने आदि की स्वतंत्रता के साथ सभी राज्यों के लिए खुला।
  - क्षेत्र (गहरा समुद्र तल): इसे और इसके संसाधनों को "मानव जाति की साझी विरासत" घोषित करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** इसमें समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के दायित्व शामिल हैं।
- **समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान:** नियम स्थापित करता है और समुद्री अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **विवाद निपटान:** विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है, जिसमें **समुद्री कानून के लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) भी शामिल है।**

- मार्च 2024 में, **भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने** मनीला की अपनी यात्रा के दौरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में फिलीपींस के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।
- **मनीला और बीजिंग के बीच दक्षिण चीन या पश्चिम फिलीपीन सागर** पर चल रहे विवाद के बीच आया है , जिसमें 2023 में तनाव और राजनयिक घर्षण बढ़ गया था।
- 2023 में, **नई दिल्ली और मनीला के बीच एक संयुक्त बयान में चीन से नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का पालन करने और 2016 में मनीला के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करने का भी आग्रह किया गया था।**
- ये बयान दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के पिछले सतर्क और तटस्थ रुख में बदलाव का संकेत देते हैं।

- भारत का विकसित होता दृष्टिकोण अपनी पिछली स्थिति से विचलन को दर्शाता है और दक्षिण चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों का समर्थन करने के साथ अधिक निकटता से जुड़ता है।
- दक्षिण चीन सागर पर भारत के रुख में यह बदलाव वैश्विक मंच पर इसकी व्यापक रणनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को दर्शाता है।

एक नीति विकास

- **प्रारंभ में, इस क्षेत्र के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव मुख्य रूप से आर्थिक था, जो उसकी पूर्व की ओर देखो नीति से प्रेरित था।**
- पूर्व की ओर देखो नीति का **उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना है।**
- जैसे भारतीय राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों ने **वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं में भाग लिया,** क्षेत्र में भारत की आर्थिक हिस्सेदारी का संकेत।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून , विशेषकर यूएनसीएलओएस **की सीमा के भीतर समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया।**
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन के तहत, भारत की नीति अभिविन्यास **लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में स्थानांतरित हो गया** , जो एक **अधिक रणनीतिक और सक्रिय जुड़ाव का प्रतीक है।** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ.
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी **न केवल आर्थिक एकीकरण बल्कि** वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस सहित इंडो-पैसिफिक के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और विस्तारित सुरक्षा सहयोग पर भी जोर देती है।
- **फॉरवर्ड पोजिशनिंग, मिशन-आधारित तैनाती, सुदृढ़ समुद्री डोमेन जागरूकता और गहरे पानी की समुद्री सुविधाओं के विकास** जैसे उपायों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को मजबूत किया है ।

चीन के साथ भारत के जटिल संबंध

- **चीन के मुखर क्षेत्रीय दावों और सैन्यीकरण प्रयासों** के कारण दक्षिण चीन सागर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है ।
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख समय के साथ अधिक सूक्ष्म और कम सतर्क हो गया है।
- भारत की स्थिति **चीन के साथ उसके जटिल संबंधों से प्रभावित है, जिसका सीमा विवादों और क्षेत्रीय घुसपैठ का इतिहास रहा है।**
- के बाद तनाव बढ़ गया , **जिसके कारण भारत को दक्षिण चीन सागर में अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत भेजकर अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना पड़ा।**
- दक्षिण चीन सागर और भारत की भूमि सीमा पर चीन की आक्रामक मुद्रा और क्षेत्रीय दावों का क्षेत्रीय स्थिरता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ता है।
- **भारत ने नियमित नौसैनिक अभ्यास और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सैन्य सहयोग सहित रणनीतिक साझेदारी में शामिल होकर जवाब दिया है।**
- ये संलग्नक दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: वे **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्र में चीन के गैरकानूनी दावों के प्रतिकार के रूप में कार्य करते हैं।**

आसियान कारक

PatrioticIAS

आसियान

- **क्षेत्रीय संगठन:** 1967 में बैंकॉक घोषणा के साथ स्थापित, आसियान एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

- **मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया.
- **वर्तमान सदस्यता:** 10 दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र:
    - ब्रूनेइ दारएस्सलाम
    - कंबोडिया
    - इंडोनेशिया
    - लाओ पीडीआर
    - मलेशिया
    - म्यांमार
    - फिलिपींस
    - सिंगापुर
    - थाईलैंड
    - वियतनाम

मूल उद्देश्य

- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता:** संघर्ष को रोकने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और सहयोग का निर्माण करें।
- **आर्थिक समृद्धि:** मुक्त व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से एकल बाजार और उत्पादन आधार बनाएं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक विकास:** मानव विकास, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

प्रमुख तंत्र

- **आसियान शिखर सम्मेलन:** व्यापक दिशा-निर्देश तय करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष साल में दो बार मिलते हैं।
- **क्षेत्रीय निकाय:** व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए जिम्मेदार विभिन्न मंत्रिस्तरीय और तकनीकी निकाय।
- **आसियान समुदाय:** 2015 में स्थापित, इसमें तीन स्तंभ शामिल हैं:
    - आर्थिक स्तंभ (एईसी)
    - सुरक्षा स्तंभ (एपीएससी)
    - सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभ (एएससीसी)

हाल के फोकस क्षेत्र

- **इंडो-पैसिफिक आउटलुक:** बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता को बढ़ावा देना।
- **सतत विकास:** जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताओं और आपदा लचीलेपन को संबोधित करना।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** आर्थिक विकास और समावेशिता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

PatrioticIAS

- **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी):** आसियान सदस्यों और अन्य एशिया-प्रशांत देशों सहित व्यापक मुक्त व्यापार समझौता।

- नई दिल्ली का रणनीतिक बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक समुद्री व्यवस्था के लिए दक्षिण चीन सागर के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानने से प्रेरित है।
- दक्षिण चीन सागर में विवादों में चीन और आसियान देश शामिल हैं, **जो नेविगेशन और निरीक्षण की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जो भारत के व्यापार और ऊर्जा परिवहन मार्गों और वैश्विक देशों के लिए महत्वपूर्ण है।**
- एक जिम्मेदार इंडो-पैसिफिक हितधारक के रूप में भारत को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि इसकी परिधि हिंद महासागर से परे व्यापक समुद्री क्षेत्र तक फैली हुई है, जिसे चीन के उदय से चुनौती मिली है।
- क्षेत्रीय समूह के भीतर चुनौतियों का सामना करने वाले आंतरिक मतभेदों के बावजूद, **भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में आसियान केंद्रीयता को कायम रखना आवश्यक है।**
- **क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध करते हुए,** नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था की वकालत करता है।
- भारत का रुख अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण चीन सागर में **चीन के विस्तृत क्षेत्रीय दावों और गतिविधियों को चुनौती देता है , जो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में स्थापित करता है।**
- दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण **भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान में योगदान करते हुए अपने हितों की रक्षा करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।**

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER II: आईआर

प्रश्न : दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर सतर्क दृष्टिकोण से लेकर अधिक मुखर स्थिति तक, विशेष रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, भारत के बदलते रुख का विश्लेषण करें। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी भारत-प्रशांत क्षेत्र में उसके व्यापक भू-राजनीतिक हितों और सुरक्षा चिंताओं को कैसे दर्शाती है? (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण

- विवादों के प्रति भारत के ऐतिहासिक सतर्क दृष्टिकोण और क्षेत्र में आर्थिक साझेदारी पर इसके प्रारंभिक फोकस के साथ उत्तर प्रस्तुत करें।
- फिर निम्नलिखित क्षेत्रों के कवरेज के साथ दक्षिण चीन सागर पर भारत के बदलते रुख को सामने लाएँ:
  - आर्थिक फोकस से लेकर रणनीतिक जुड़ाव तक
  - बढ़ती मुखरता
  - UNCLOS पर जोर
- यह दोहराते हुए निष्कर्ष निकालें कि यह कैसे अपने स्वयं के सुरक्षा हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय शांति में योगदान करने और चीनी विस्तारवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने की भारत की इच्छा को दर्शाता है।

उत्तर

PatrioticIAS

दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के रुख में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है, विशेष रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह सतर्क दृष्टिकोण से अधिक मुखर रुख में परिवर्तित हो गया है। प्रारंभ में, इस क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव मुख्य रूप से आर्थिक विचारों से प्रेरित था, जैसा कि इसकी पूर्व की ओर देखो नीति से स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना था।

- ओएनजीसी विदेश जैसे भारतीय राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों ने वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं में भाग लिया, जो इस क्षेत्र में भारत की आर्थिक हिस्सेदारी का संकेत देता है।
- हालाँकि, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन के तहत, भारत की नीति अभिविन्यास लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में स्थानांतरित हो गई, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक और सक्रिय जुड़ाव का प्रतीक है।
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी न केवल आर्थिक एकीकरण पर जोर देती है, बल्कि वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस सहित इंडो-पैसिफिक के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और विस्तारित सुरक्षा सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- यह बदलाव भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के व्यापक भू-राजनीतिक हितों और सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है।
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का विकसित होता दृष्टिकोण क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक समुद्री व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण महत्व की उसकी मान्यता को भी दर्शाता है।
- दक्षिण चीन सागर में चीन और आसियान देशों से जुड़े विवाद नेविगेशन और निरीक्षण की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जो भारत के व्यापार और ऊर्जा परिवहन मार्गों और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार इंडो-पैसिफिक हितधारक के रूप में, भारत को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि इसकी परिधि हिंद महासागर से परे व्यापक समुद्री क्षेत्र तक फैली हुई है, जिसे चीन के उदय से चुनौती मिली है।
- दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का रणनीतिक जुड़ाव नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था की वकालत, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) पर जोर देना और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध करना है।
- भारत का रुख अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तृत क्षेत्रीय दावों और गतिविधियों को चुनौती देता है, जो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में स्थापित करता है।

- इसके अलावा, दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण, जो इसके पहले के सतर्क रुख से हटकर और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों का समर्थन करने के साथ संरेखित है, भारत में शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। -प्रशांत क्षेत्र.
- क्षेत्रीय समूह के भीतर आंतरिक मतभेदों के कारण चुनौतियां उत्पन्न होने के बावजूद, भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में आसियान केंद्रीयता को बरकरार रखना आवश्यक है।

इस प्रकार, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी भारत-प्रशांत क्षेत्र में उसके व्यापक भू-राजनीतिक हितों और सुरक्षा चिंताओं को दर्शाती है, जो सामान्य चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देती है।

PatrioticIAS